पटना के उच्च न्यायालय में

पूर्ण पीठ

1968 की एस.सी.ए. सं. 244

ने निर्णय लियाः 21.01.1970

याचिकाकर्ता: **सुधीर चंद्र सरकार**

बनाम

उत्तरदातागण: **टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और अन्य**

[एस. सी. ए. सं. 255 के साथ]

माननीय न्यायाधीश/कोरमः

एस. सी. मिश्रा, मुख्य न्यायमूर्ति, उदय सिन्हा और ए.बी.एन. सिन्हा, न्यायमूर्तिगण

वकील:

याचिकाकर्ता के लिए: श्री एस. के. मजूमदार

उत्तरदाताओं के लिए: लाल नारायण सिन्हा और एल. के. चौधरी

भारत का संविधान - अनुच्छेद 133(1)(सी)- अपील के लिये प्रमाण पत्र

सिविल प्रक्रिया संहिता - वादों का समर्थन

आदेश XLV नियम 4 - अपील के लिये प्रमाण पत्र दोनों अपीलकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 133(1)(सी) के तहत अपने अपील के प्रमाण पत्र के लिये आवेदन दायर किए है लेकिन बहस के समय केवल समेकन के प्रश्न पर जोर दिया गया था और इसके तहत प्रमाण पत्र देने के लिए कोई तर्क नहीं दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 133(1)(सी) परिणामस्वरुप दो मामलों में प्रमाण पत्र अस्वीकार कर दिए जाते हैं।

[पारा 4]

पटना के उच्च न्यायालय में

पूर्ण पीठ

1968 की एस.सी.ए. सं. 244

ने निर्णय लियाः 21.01.1970

याचिकाकर्ता: **सुधीर चंद्र सरकार**

बनाम

उत्तरदातागण: **टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और अन्य**

[एस. सी. ए. सं. 255 के साथ]

माननीय न्यायाधीश/कोरमः

एस. सी. मिश्रा, मुख्य न्यायमूर्ति, उदय सिन्हा और ए.बी.एन. सिन्हा, न्यायमूर्तिगण

वकील:

याचिकाकर्ता के लिए: श्री एस. के. मजूमदार

उत्तरदाताओं के लिए: लाल नारायण सिन्हा और एल. के. चौधरी

निर्णय

उदय सिन्हा, न्यायमूर्ति

1. ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन हैं, इस न्यायालय के 6 अगस्त, 1968 के निर्णय जो प्रथम अपील सं. 1963 का 444 और 1964 का संख्या 554 में पारित किये गए थे। श्री सुधीर चंद्र सरकार, धन वाद सं. 1962 के 452 ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 133 (1) (सी) के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 109 और 110 के तहत एक आवेदन दायर किया है और मामले को सर्वोच्च न्यायालय

की अपील संख्या के रूप में क्रमांकित गया है 1968 का 244। श्री बंटवाल बासुदेव माल्या, धन वाद मुकदमा नं. 1963 के 900, एक अलग व्यक्ति ने भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 133 (1) (सी) के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 109 और 110 के तहत एक आवेदन दायर किया है और मामले को सर्वोच्च न्यायालय की अपील संख्या- 968 का 255 के रूप में क्रमांकित किया गया है। उच्चतम न्यायालय में अपील सं. 1968 का 255 आदेश XLV (45) नियम 4 और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें अनुरोध किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की दो अपीलों को समरुप बनाया जा सकता है और आर्थिक अधिकार क्षेत्र के उद्देश्य से समेकित किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक सूट का मूल्य रुपये से कम था। 20, 000। जिन तथ्यों पर विचार करने का सवाल उठा है, वे इस प्रकार हैं; श्री सुधीर चंद्र सरकार ने 16,498.18 रुपये की वसूली के लिए धन वाद दायर किया था। अवैतनिक उपदान देय राशि के कारण प्रतिवादियों के खिलाफ श्री अरबिंद मुखर्जी, अधीनस्थ न्यायाधीश, जमशेदपुर द्वारा 17 मई, 1963 को मुकदमे का फैसला सुनाया गया था, श्री बंटवाल बासुदेव माल्या ने 11, 550/- रुपये की वसूली के लिए अपना धन मुकदमा लाया था। प्रतिबादी के खिलाफ ग्रेच्युटी बकाया के कारण और 10 सितंबर 1964 को श्री रामावतार लाल दास, जो उस समय जमशेदपुर में अधीनस्थ न्यायाधीश थे, द्वारा मुकदमा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, श्री सरकार के मुकदमे में से 1 ने प्रथम अपील सं.- 1963 का 444 और श्री माल्या ने प्रथम अपील सं.- 1964 का 554। दोनों अपीलों की सुनवाई इस न्यायालय द्वारा एक साथ की गई थी और 6 अगस्त, 1968 को पारित एक सामान्य निर्णय द्वारा, प्रथम अपील सं. 1963 का 444 स्वीकृत किया गया था और प्रथम अपील सं. 1964 का 554 खारिज कर दिया गया। नतीजतन, श्री सुधीर चंद्र सरकार का मुकदमा इस अदालत के फैसले और डिक्री से विफल हो गया और श्री माल्या के मुकदमे को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार श्री

सुधीर चंद्र सरकार और श्री बंटवाल बासुदेव ने ऊपर उल्लिखित दो सर्वोच्च न्यायालय की अपीलें दायर की हैं।

2. अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने दायर अपने आवेदन पर भरोसा किया है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLV (45) नियम 4 के तहत, यह आग्रह करते हुए कि दोनों अपीलें इस न्यायालय के एक ही फैसले द्वारा शासित हैं, जिसमें कानून का एक ही बिंदु शामिल है और अपीलों पर आसानी से एक साथ निर्णय लिया जा सकता है और उन्होंने प्रार्थना की है कि आर्थिक अधिकार क्षेत्र के उद्देश्य से दोनों मामलों को समेकित किया जा सकता है। विचाराधीन कानून का सवाल यह है कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLV (45) नियम 4 इस तरह के समेकन की अनुमति देगा।

3. सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश XLV नियम 4 इस प्रकार हैः--

> आर्थिक मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, निर्णय के लिए समान प्रश्नों को शामिल करने वाले और एक ही निर्णय द्वारा तय किए गए मुकदमों को समेकित किया जा सकता है, लेकिन अलग-अलग निर्णयों द्वारा तय किए गए मुकदमों को एकीकृत नहीं किया जाएगा; भले ही उनमें निर्धारण के लिए काफी हद तक समान प्रश्न शामिल हो।

अपीलकर्ताओं की ओर से (1) देवकीनंदन प्रसाद बनाम नरसिंह राउत के मामले में 6 पी. एल. जे. 97 में रिपोर्ट किए गए और 31 अक्टूबर, 1962 को इस न्यायालय द्वारा पारित समेकन के आदेश पर (2) उच्चतम न्यायालय की अपील सं. 1962 का 56.अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने अन्य उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णयों का भी उल्लेख किया है, जिनका संदर्भ उचित समय पर दिया जाएगा। नियत समय पर। देवकिनंदन प्रसाद के मामले की मुख्य विशेषताएं (6 पी. एल. जे. 97)। ए. आई. आर. 1921 पैट 97) ये हैं। पटना के अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा कुल 49 मुकदमों की सुनवाई की गई थी। इनमें से केवल एक सूट का मूल्य रुपये से अधिक था। 10,000/- वह मुकदमा खारिज कर दिया गया था और

उच्च न्यायालय में वादी द्वारा दायर अपील विफल हो गई थी। कुछ अन्य मुकदमों में निचली अपील अदालत के समक्ष अपील दायर की गई थी और निचली अदालत के आदेशों की पुष्टि की गई थी। इसके बाद, इस न्यायालय में कई द्वितीय अपील दायर की गई थी और इस न्यायालय ने जिला न्यायाधीश के फैसले की पुष्टि की थी। चौदह मामलों में से समेकन का सवाल उठा था, जिसका कुल मूल्यांकन रु. 7,290/- था। आर्थिक मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए इस न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLV नियम 4 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने और इन चौदह मुकदमों को एकमात्र मुकदमे के साथ समेकित करने के लिए कहा गया था, जिसका मूल्य रु. 10,000/- से ज्यादा था। उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता का तर्क था कि चूंकि सभी मुकदमों का फैसला पहली अदालत में एक ही फैसले द्वारा किया गया था और (इस प्रकार से) आदेश XLV नियम 4 का प्रावधान उनके लिए उपलब्ध था। कानून के इस प्रावधान की व्याख्या पर इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा;--

> उस नियम 1 को पढ़कर मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल हो सकता है, लेकिन वहां इस्तेमाल किया गया निर्णय शब्द उस फैसले को संदर्भित करता है जिसके खिलाफ अपील की गई थी। अर्थात यह वह निर्णय है जिस पर नियम 4 में विचार किया जा रहा है और यह सुझाव देने के लिए कि चूंकि मुकदमे मूल रूप से पहली बार किसी निर्णय पर निर्णय लेने वाली अदालत में थे, इसलिए बाद में उनके साथ जो कुछ भी हुआ हो और क्या अंततः उच्च न्यायालय में उसी निर्णय या कई निर्णयों द्वारा निर्णय लिया गया हो, ऐसे मामले में परिषद में महामहिम को अपील करने के उद्देश्य से समेकित करने की शक्ति होनी चाहिए, मेरी राय में आदेश XLV, नियम 4 को एक अर्थ देना है जिसे वह कभी सहन नहीं करना चाहता था। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस निर्णय पर उनके अधिपतियों को विचार करना है और जिससे अपील की जाती है, वह समेकित अपीलों में एक ही निर्णय होना चाहिए, न कि यह कि उन्हें

एक ही मामले में या एक ही अपील में उच्च न्यायालय के कई अलग-अलग निर्णयों के प्रभाव पर विचार करना चाहिए।

इस प्रकार, याचिकाकर्ता समेकन का आदेश प्राप्त करने में विफल रहे। 31 अक्टूबर, 1962 के आदेश से प्रकट होने वाले मुख्य तथ्य जो इस न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अपील सं. 1962 का 56 ये हैं; उस अपील के समेकन के लिए दायर एक आवेदन पर उच्चतम न्यायालय की अपील सं। 1962 का 75 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि यद्यपि विचारण न्यायालय के समक्ष दायर दो स्वामित्व वादों की सुनवाई की गई थी और अलग-अलग निर्णय लिया गया था, उच्च न्यायालय ने दोनों प्रथम अपीलों पर एक ही निर्णय द्वारा विचार किया था और इसलिए, प्रश्नगत दोनों वादों को आदेश XLV नियम 4 के तहत समेकित किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय के तहत दोनों अपीलों को एक ही निर्णय द्वारा निपटाया जाता है, आदेश XLV का प्रावधान नियम 4 संतुष्ट था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देवकी नंदन प्रसाद के मामले में पारित आदेश अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क का समर्थन करता है, लेकिन उसमें व्यक्त विचार को बनाए रखना शायद ही संभव है। नियम 4 ऑर्डर XLV के शब्द स्पष्ट हैं जब यह कहा जाता है कि सूट में काफी हद तक समान प्रश्न शामिल हैं। निर्धारण और उसी निर्णय द्वारा निर्णय को समेकित किया जा सकता है। "यहाँ निर्णय को मुकदमों में निर्णय को संदर्भित करना चाहिए। इसे नियम के दूसरे भाग द्वारा स्पष्ट किया गया है जहां नकारात्मक पहलू पर जोर दिया गया है, ताकि अलग-अलग निर्णयों द्वारा तय किए गए मुकदमों को समेकित नहीं किया जा सके, इसके बावजूद कि उनमें निर्धारण के लिए काफी हद तक एक ही प्रश्न शामिल हैं। "नियम के इस भाग में दिखाई देने वाले निर्णय स्पष्ट रूप से इन निर्णयों को संदर्भित करते हैं सूट इसलिए, आदेश XLV नियम 4 में दिखाई देने वाले "निर्णय" और "निर्णय" शब्दों को मुकदमों में पारित निर्णय या निर्णयों को संदर्भित करना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि ऑर्डर XLV

का नियम 4 मुकदमों के समेकन को संदर्भित करता है और इसके खिलाफ अपील किए गए निर्णय या निर्णयों के महत्व को आयात करने का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय की अपील सं. में पारित आदेश। 1962 के 56 में विचाराधीन प्रश्न पर कोई विस्तार से चर्चा नहीं की गई है। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की दो अपीलों में विचाराधीन दो मुकदमों का फैसला दो अलग-अलग अधीनस्थ न्यायाधीशों द्वारा अलग-अलग तारीखों पर दो अलग-अलग निर्णयों द्वारा किया गया था और इस न्यायालय के आदेश से यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि आदेश XLV नियम 4 की व्याख्या पर क्या तर्क दिए गए थे। 31 अक्टूबर, 1962 के आदेश द्वारा इस न्यायालय द्वारा समेकित दो अपीलों को उच्चतम न्यायालय के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि अभिलेख से पता चलता है, और इसलिए, हम नहीं जानते कि उच्चतम न्यायालय ने समेकन के प्रश्न पर क्या दृष्टिकोण अपनाया होगा। अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने मद्रास उच्च न्यायालय के दो फैसलों पर भरोसा किया है जो (2) मनु/टी. एन./0132/1931 में रिपोर्ट किए गए हैंःए. आई. आर. 1932 मैड 125 और (4) ए. आई. आर. 1949 मैड 739 (एफ. बी.)। (3) (श्री राजा) वसी रेड्डी श्रीचंद्र मौलेश्वर प्रसाद बहादुर जमींदार गारू वी. सचिव का मामला। राज्य और अन्य (मनु/टी. एन./0132/1931:ए. आई. आर. 1932 मैड 125), 6 पी. एल. जे. 97 ए. आई. आर. 1921 पैट 97 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के निर्णय का पालन संहिता के आदेश XLV नियम 4 में आने वाले "निर्णय" शब्द के अर्थ पर किया गया था। इस न्यायालय के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस अभिव्यक्ति का अर्थ उस निर्णय से है जिसके खिलाफ अपील की गई थी। लेकिन वसी रेड्डी का मामला काफी अलग है, क्योंकि वहां यह माना गया था कि दो अलग-अलग मुकदमों के दो अलग-अलग फैसले विचाराधीन हैं। वास्तव में यह निचली अदालत के एक फैसले के बराबर था। मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि पहली अदालत के तथाकथित अलग-अलग फैसलों की तुलना से पता चलता है कि दूसरा फैसला व्यावहारिक

रूप से पहली अदालत के फैसले की एक प्रति थी, जिसमें कुछ वाक्यों या पैराग्राफ को छोड़ दिया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस प्रकार के मामले में नियम 4 की भावना को समाहित किया जाना चाहिए और निचली अदालत के दो निर्णयों को एक ही निर्णय के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए, वसी रेड्डी का मामला अपीलार्थियों के विद्वान वकील के लिए सहायक नहीं है। (4) मोलुगु लक्ष्मीनरसिंह चरयुलु और अन्य के मामले में वी. मारिसेट्टी रत्नम और अन्य [(एफ. बी.) ए. आई. आर. 1949 मैड। 739)], मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने उपरोक्त मद्रास निर्णय को मंजूरी दी। लेकिन इस मामले को भी उसी आधार पर अलग किया जा सकता है जिस पर मैंने माना है कि वसी रेड्डी का मामला अपीलार्थीयों को सहायता नही देता है। मोलुगु के मामले में भी, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निचली अदालत द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णय वास्तव में एक ही निर्णय थे। मनु/एन. ए./0003/1956 में रिपोर्ट किए गए (5) किशनलाल नंदलाल और एक अन्य बनाम विठ्ठल नागय्या के मामले का भी यही आधार हैःए. आई. आर. 1956 नाग 276, अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा करना उनके लिए सहायक नहीं है। नागपुर उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश भी इस आधार पर आगे बढ़े थे कि एकीकरण का आदेश दिया जा सकता है यदि अलग-अलग निर्णय काफी हद तक समान हों। अन्य उच्च न्यायालयों के कई निर्णय हैं जिनमें कहा गया है कि संहिता के आदेश XLV नियम 4 की व्याख्या करने में, विचार के लिए प्रासंगिक बिंदु निचली अदालत का निर्णय है। श्री होरी लाल और एक अन्य बनाम राजस्व बोर्ड, यू. पी. इलाहाबाद और अन्य के मामले (6) में मनु/यू. पी./0028/1960 में रिपोर्ट कियाःए. आई. आर. 1960 अल्ला 133 मनु/टी. एन./0132/1931 में बताए गए निर्णयःए. आई. आर. 1932 मैड 125, ए. आई. आर. 1949 मैड। 739 (FB) और (5) मनु/एन.ए./0003/1956 मेंःए. आई. आर. 1956 नाग। सभी 276 पर विचार किया गया है। मद्रास और नागपुर उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त विचार इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दो अलग-अलग निर्णयों की पहचान

को मंजूरी नहीं दी गई थी जो उन्हें एक और एक ही बनाते हैं। हालांकि, 1 ने मद्रास और नागपुर के फैसलों को अलग करते हुए कहा है कि वे हमारे समक्ष मुद्दे पर निर्णय लेने के उद्देश्य से अपील के लिए सहायक नहीं हैं और तथ्यों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगला मामला जिस पर चुनाव लड़ने वाले विरोधी पक्ष की ओर से हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है, वह (7) फर्म किशोरी लाल जगन्नाथ पी. डी. का मामला है। बनाम फर्म मुरलीधर बनवारीलाल ने आई.एल.आर. मनु/आर.एच./0075/1960 में बतायाः(1961) 11 राज 735। निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे उद्धृत किया जा सकता हैः--

> आदेश XLV नियम 4, सिविल प्रक्रिया संहिता के निर्माण के बारे में न्यायिक राय में कुछ भिन्नता प्रतीत होती है। बार में उद्धृत विभिन्न मामलों पर चर्चा करना व्यर्थ है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इसके बावजूद अपीलार्थी नियम के लाभ के हकदार नहीं हैं और इस मामले की परिस्थितियों में मुकदमों का कोई समेकन नहीं हो सकता है। स्पष्ट रूप से जैसा कि नियम की भाषा से पता चलता है कि यह केवल उन मामलों पर लागू होता है जहां मुकदमों का निर्धारण और निर्णय एक सामान्य निर्णय द्वारा किया गया है और निर्धारण के लिए काफी हद तक वही प्रश्न शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि नियम में 'अपील' शब्द का उपयोग किया गया है। विधायिका के दिमाग में 'अपील' के बजाय 'वाद' शब्द का उपयोग करने का एक निश्चित उद्देश्य था और यदि विचार यह था कि अपीलों में भी जहां उन्हें उसी निर्णय द्वारा निपटाया गया था और निर्धारण के लिए काफी हद तक वही प्रश्न शामिल थे, तो उपरोक्त नियम लागू होगा, विधायिका आसानी से ऐसा कह सकती थी और इसके अर्थ को प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त अभिव्यक्तियाँ। इसलिए हम हैं, स्पष्ट रूप से यह राय है कि ओ. एक्स. एल. वी. के आर. 4 का इस तरह के मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। यह केवल सुविधा के लिए है कि हमने दोनों अपीलों को एक साथ सुना, अन्यथा दोनों

मुकदमे पूरी तरह से अलग थे और सभी प्रारंभिक चरणों में सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए अलग-अलग व्यवहार किया गया था। इसलिए हम सोचते हैं कि इस मामले में धारा 110 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है।

मैं यह उल्लेख कर सकता हूं कि राजस्थान मामले में उच्च न्यायालय में अपीलों का भी अलग-अलग निर्णयों द्वारा अलग-अलग निपटारा किया गया था, लेकिन तत्काल निर्णयों में विवादग्रस्त मामले के निपटारे के लिए, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार को मंजूरी देना आवश्यक है, जिसमें कहा गया है कि आदेश XLV, नियम 4 लागू होगा जहां मुकदमे स्वयं निर्धारित किए गए हैं और निर्णय के लिए एक ही प्रश्न को शामिल करते हुए एक सामान्य निर्णय द्वारा तय किया गया है। (4) खुशी राम रेलू राम बनाम श्रीमान भागो और एक अन्य का मामला। ए. आई. आर. 1956 में दर्ज पुन 32 भी सही है। इस मामले में मनु/टी.एन./0132/1931 में बताए गए निर्णयः ए. आई. आर. 1932 मैड 125 और ए. आई. आर. 1949 मैड। 739 (एफ. बी.) को अलग किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब पहली बार में अलग-अलग अदालतों द्वारा दो मुकदमों की सुनवाई की गई थी, तो संहिता के आदेश XLV नियम 4 के तहत समेकन की अनुमति नहीं थी।

4. पक्षों की ओर से उठाए गए विवाद पर विचार करने पर, मेरा विचार है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLV नियम 4 के तहत इन मामलों में आर्थिक मूल्यांकन के उद्देश्य से दो मुकदमों का एकीकरण नही किया जा सकता है और इस आशय की प्रार्थना अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। मैंने उल्लेख किया है कि दोनो अपीलकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 133(1)(c) के तहत अपने अपील के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दायर किए है लेकिन बहस के समय केवल समेकन के प्रश्न पर जोर दिया गया था और इसके तहत प्रमाण पत्र देने के लिए कोई तर्क नही दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 133(1)(सी) परिणामस्वरुप दो मामलों में प्रमाण पत्र अस्वीकार कर दिए जाते है। लागत के लिए कोई आदेश नही होगा।

एस. सी. मिश्रा, न्यायमूर्ति

मैं सहमत हूँ।

ए.बी.एन सिन्हा, न्यायमूर्ति

मैं सहमत हूँ।

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।